

महत्त्वपूरण खनजिं की पहेली

यह एडटोरियल 05/03/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Why Minerals Are Critical" लेख पर आधारित है। इसमें महत्त्वपूरण खनजिं तक पहुँच की अप्रयाप्तता और उन्हें संसाधनी करने एवं अंतमि उत्पाद के नियम के लिये प्रौद्योगिकी तक पहुँच की आवश्यकता के संबंध में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

महत्त्वपूरण खनजि, खनन क्षेत्र, दुर्लभ मृदा धातु, खान और खनजि (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, भारतीय भूवैज्ञानिक संस्करण (GSI), इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, खनजि सुरक्षा साझेदारी।

मेन्स के लिये:

भारत के लिये महत्त्वपूरण खनजिं का महत्त्व, भारत में खनजि वितरण।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में **महत्त्वपूरण खनजिं (Critical Minerals)** के विषय में दो महत्त्वपूरण कदम उठाये गए। पहला कदम यह रहा कि जुलाई 2023 में 30 महत्त्वपूरण खनजिं (**दुर्लभ मृदा तत्त्व**) के अलावा, जिन्हें आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है। की एक सूची की पहचान की गई, जबकि दूसरा कदम यह रहा कि महत्त्वपूरण खनजिं/दुर्लभ मृदा तत्त्वों के 20 बलॉकों की नीलामी में नियमीकृत की भागीदारी की अनुमति देने के लिये नवंबर 2023 में मौजूदा खनन कानूनों में संशोधन किया गया।

खान और खनजि (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023:

- मूल अधिनियम (वर्ष 1957 का अधिनियम) के तहत कुछ नियमित मामलों को छोड़कर रियायतों की नीलामी राज्य सरकारों द्वारा की जाती थी।
- वर्ष 2023 के संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि नियमित महत्त्वपूरण एवं रणनीतिक खनजिं के लिये समग्र लाइसेंस और खनन पट्टे की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी।
- इन खनजिं में लथियम, कोबाल्ट, निकेल, फॉस्फेट, पोटाश, टनि आदि शामिल हैं। हालाँकि रियायतें अभी भी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएँगी।

दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements- REEs):

- दुर्लभ पृथकी तत्व आवर्त सारणी में 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है—वशिष्ठ रूप से स्कैंडियम (scandium) और येट्रियम (yttrium) के साथ 15 लैथनाइड्स (lanthanides) का समूह। दुर्लभ मृदा तत्व जैसे उनके नाम के बावजूद वस्तुतः वे पृथकी के क्रस्ट में अपेक्षित प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी ऐसी सांदर्भता में पाए जाते हैं कि उनका आरथिक रूप से दोहन किया जा सके।
- REEs में कुछ वशिष्ठ गुण पाए जाते हैं जो उन्हें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, वडि टरबाइन और रक्षा प्रणालियों सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों की एक वित्त शृंखला में महत्त्वपूरण घटक बनाते हैं। उनका उपयोग चुंबक, उत्प्रेरक (catalysts), फॉस्फोरस और ऐसे कई अन्य अनुपरयोगों में किया जाता है जहाँ उनके वशिष्ठ गुण आवश्यक होते हैं।

महत्त्वपूरण खनजि (Critical Minerals) क्या हैं?

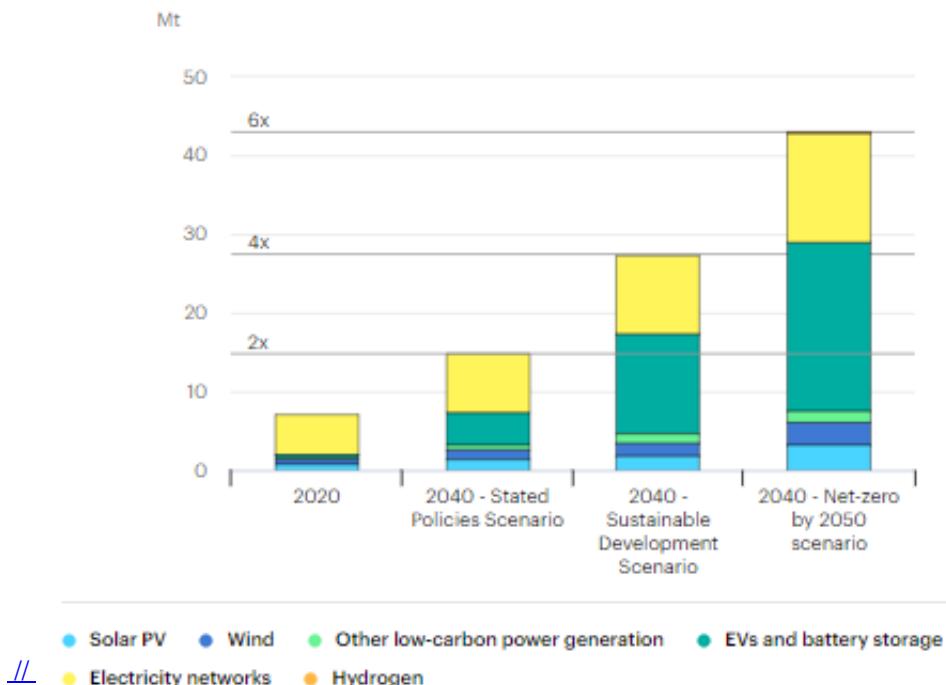
- परचिय:**
- महत्त्वपूरण खनजि ऐसे खनजि हैं जो आरथिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं; इन खनजिं की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में नाशक्रिया या प्रसंस्करण की एकाग्रता से आपूर्ति शृंखला की भेद्यता और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- महत्त्वपूरण खनजिं की कोई वशिष्ठ परभिषा नहीं है और विभिन्न देश अपने स्वयं के मानदंडों का उपयोग कर अपने लिये महत्त्वपूरण खनजिं की पहचान करते हैं।
- महत्त्वपूरण खनजिं की घोषणा:**
- यह एक गतशील प्रक्रिया है और यह समय के साथ नई प्रौद्योगिकियों, बाजार की गतशीलता एवं भू-राजनीतिक विचारों के उभार के साथ विकसित हो सकती है।

- वभिन्न देशों के पास अपनी वशिष्ट परस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्वपूरण खनजिं की अपनी वशिष्ट सूची हो सकती है।
- अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक विकास में कुछ खनजिं की भूमिका के मददेनजर 50 खनजिं को महत्वपूरण खनजि घोषित किया है।
- जापान ने 31 खनजिं के एक समूह को अपनी अरथव्यवस्था के लिये महत्वपूरण खनजि माना है।
- इसी प्रकार, यूके ने 18, [यूरोपीय संघ](#) ने 34 और कनाडा 31 खनजिं को महत्वपूरण खनजि घोषित किया है।
- **भारत के लिये महत्वपूरण खनजि:**
- भारत ने अपने महत्वपूरण खनजिं की पहचान उनकी व्यवधान क्षमता, प्रतिस्थापन क्षमता, वभिन्न क्षेत्रों में क्रॉस-कटिंग उपयोग, आयात नियन्त्रिता, पुनर्चक्रण दरों आदि के आधार पर की है।
- खान मंत्रालय के तहत वशिष्ट समिति ने भारत के लिये **30 महत्वपूरण खनजिं** के एक समूह की पहचान की है। इनमें शामिल हैं:
 - एंटीमीनी, बेरलियम, बस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्राफाइट, हेफनियम, इंडियम, लथियम, मोलबिडेनम, नायोबियम, निकिल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, REE, रेनियम, सलिकिन, स्ट्रोटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टनि, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़रिकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।
 - जनि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ये **30 चहिनति महत्वपूरण खनजि** पाए जाते हैं, वे हैं: बहिर, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर।
- समिति ने खान मंत्रालय के तहत महत्वपूरण खनजिं के लिये उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Critical Minerals (CECM) के गठन की भी सफ़िकारशि की है। CECM आवधिकि रूप से भारत के लिये महत्वपूरण खनजिं की सूची को अद्यतन करेगा और समय-समय पर महत्वपूरण खनजि रणनीतिको अधिसूचिति करेगा।

वशिव भर में महत्वपूरण खनजिं के लिये वरतमान परदृश्य क्या है?

- **महत्वपूरण खनजिं की मांग और बाजार में तेज़ वृद्धि:**
 - वर्ष 2017 से 2022 के बीच लथियम की मांग में तीन गुना वृद्धि हुई, जबकि कोबाल्ट की मांग में 70% और निकिल की मांग में 40% की वृद्धि देखी गई। इन खनजिं की मांग में वृद्धि मुख्यतः [ऊरजा कषेत्र](#) की मांग से अधिकरिता थी।
 - [अंतर्राष्ट्रीय ऊरजा एजेंसी \(IEA\)](#) ने अनुमान लगाया है कि [परेसि समझौते](#) के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अगले दो दशकों में महत्वपूरण खनजिं की कुल मांग में स्वच्छ ऊरजा प्रौद्योगिकियों की हसिसेदारी तांबे एवं दुरलभ मृदा तत्वों के लिये 40%, निकिल एवं कोबाल्ट के लिये 60-70% और लथियम के लिये 90% से अधिक होगी।
 - जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये स्वच्छ ऊरजा प्रौद्योगिकियों के लिये खनजि की मांग वर्ष 2040 तक कम से कम चार गुना बढ़ जाएगी।
- **नीतिगत उपायों के माध्यम से वैश्वकि प्रयास:**
 - महत्वपूरण खनजि आपूरति की उपलब्धता ऊरजा परविरतन की वहनीयता और गताको वृहत् रूप से प्रभावित करेगी। अनश्चिति वैश्वकि आपूरति शृंखलाओं के शमन के लिये वभिन्न देश अपनी खनजि आपूरति में विधिता लाने के लिये नई नीतियाँ लागू कर रहे हैं।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने नियमक कानून बनाये हैं, जबकि इंडोनेशिया, नामीबिया और ज़मिबाब्वे जैसे संसाधन संपन्न देशों ने असाधित खनजि अयस्कों के नियत पर प्रतविधि लगाया है।
- **चुनिदा देशों में महत्वपूरण खनजिं की सांदरत्ता:**
 - ये संसाधन कुछ देशों में संकेंद्रति हैं और लथियम, कोबाल्ट एवं दुरलभ मृदा तत्वों के मामले में वशिव के शीर्ष तीन उत्पादक देश वैश्वकि उत्पादन के लगभग तीन-चौथाई भाग पर नियंत्रण रखते हैं।
 - वशिव रूप से, वशिव में ऑस्ट्रेलिया 55% लथियम भंडार, चीन 60% दुरलभ मृदा तत्व भंडार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) 75% कोबाल्ट भंडार, इंडोनेशिया 35% निकिल भंडार और चलि 30% तांबा भंडार रखता है।
- **भू-राजनीतिकि तनाव और संसाधन राष्ट्रवाद:**
 - इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूरण है क्योंकि राष्ट्रों के बीच वैश्वकि संबंध अधिकि धरुवीकृत हो गए हैं, वशिव रूप से [अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध](#) और [रुस-यूक्रेन युद्ध](#) जैसी घटनाओं के कारण। इन संघर्षों के कारण स्थापति व्यापार पैटर्न में प्रतविधि और व्यवधान की स्थितिउत्पन्न हुई है।
- **आपूरति-मांग की गतशीलता:**
 - आपूरति से अधिकि मांग की वृद्धि के कारण तांबे जैसी महत्वपूरण औद्योगिकि धातुओं की कीमतें आने वाले वर्षों में बढ़ सकती हैं। सामग्री कीमतों में इस वृद्धि से सौर पैनलों और इलेक्ट्रिकि वाहनों जैसे उपकरणों की उत्पादन लागत प्रभावित होने की संभावना है।

Total mineral demand for clean energy technologies by scenario, 2020 compared to 2040



महत्त्वपूर्ण खनजिं का क्या महत्त्व है?

- जैसा कि पूर्ववर्ती योजना आयोग ने रेखांकति किया था:
 - भारत में देश के लिये महत्त्वपूर्ण खनजिं की पहचान करने के लिये अतीत में कुछ प्रयास किये गए थे, जिनमें वर्ष 2011 में भारत के योजना आयोग की एक पहल भी शामली थी जिसने महत्त्वपूर्ण खनजिं की आवश्यकता को रेखांकति किया था।
 - उस रपोर्ट में धात्वकि, अधात्वकि, कीमती रत्नों एवं धातुओं और रणनीतिक खनजिं जैसी शरणियों के तहत खनजिं के 11 समूहों का विश्लेषण किया गया था। वर्ष 2017 से 2020 के बीच देश में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज एवं विकास के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया गया था।
- आरथकी विकास:
 - हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परविहन और रक्षा जैसे उदयोग इन खनजिं पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, सौर पैनल, पवन टरबाइन, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये भी महत्त्वपूर्ण खनजि आवश्यक हैं।
 - महत्त्वपूर्ण खनजि डीकार्बोनाइज़ेशन (decarbonisation) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं है। उत्प्रक, निर्माण, उदयोगों के लिये चुंबक, परविहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा आदिक्षेत्रों में भी इनकी आवश्यकता होती है।
 - इन क्षेत्रों में भारत की बड़ी घरेलू मांग और क्षमता को देखते हुए, उनकी वृद्धिसे रोजगार सृजन, आय सृजन और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा:
 - ये खनजि रक्षा, एयरोस्पेस, परमाणु और अंतर्रक्ष अनुप्रयोगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जहाँ चरम स्थितियों का सामना करने और जटिल कार्य करने में सक्षम उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता होती है।
 - रक्षा तत्परता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिये भारत को महत्त्वपूर्ण खनजिं की निरित आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
- प्रयावरणीय संवर्हनीयता:
 - चूंकि भारत [वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य \(net-zero by 2070\)](#) अरथव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है, इसके लिये महत्त्वपूर्ण खनजिं (और दुर्लभ मृदा तत्वों) की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाशम ईंधन बजिली उत्पादन क्षमता स्थापित करने का भी लक्ष्य रखता है।
 - भारत 30% नजिं कारों, 70% वाणिज्यिक वाहनों और 80% दो/तीन पहयि वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक्स करने की भी मंशा रखता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के वाहनों हेतु बैटरी निर्माण के लिये आवश्यक लिथियम एवं अन्य खनजिं के स्थरि स्रोत के बना यह संभव नहीं हो सकता।
- उर्धवाधर एकीकरण के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना:
 - इन खनजिं की पहचान करना औद्योगिक उत्पादन और सुदृढ़ आपूर्ति-शृंखला नेटवरक में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है क्योंकि ये खनजि विभिन्न रणनीतिक मूल्य शृंखलाओं के आवश्यक घटक हैं, जिनमें शून्य-उत्सर्जन वाहन, पवन टरबाइन एवं सौर पैनल जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहलें; सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सेमीकंडक्टर सहित); और उन्नत विनिर्माण इनपुट एवं सामग्री (जैसे रक्षा अनुप्रयोग, स्थायी चुंबक, सरिमकि आदि) शामली हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
 - इन सहयोगों से भारत को अपने आयत स्रोतों में विविधिता लाने, चीन पर निर्भरता कम करने और खनजि सुरक्षा एवं प्रत्यास्थता बढ़ाने में

सक्षमता प्राप्त हो रही है। इसने अमेरिका के नेतृत्व वाली खनजि सुरक्षा साझेदारी (Minerals Security Partnership- MSP) के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है।

- भारत भी MSP में शामिल हुआ है। MSP का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनजि आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करना है। MSP में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन एवं नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं, जिनके पास महत्वपूर्ण खनजियों के भंडार हैं, जबकि जापान एवं दक्षिणी कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं जिनके पास प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी तक पहुँच है।

भारत में महत्वपूर्ण खनजियों से संबंधित विभिन्न चिताएँ क्या हैं?

■ सीमति घरेलू भंडार:

- भारत में लथियम, कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनजियों के सीमति भंडार हैं। इनमें से अधिकांश खनजियों का आयात किया जाता है, जिससे भारत इसकी आपूर्ति के लिये अन्य देशों पर अत्यधिक निरिभर हो जाता है।
- आयात पर यह निरिभरता मूल्य में उत्तर-चंद्राव, भू-राजनीतिक कारकों और आपूर्ति में व्यवधान के मामले में भेद्यता उत्पन्न कर सकती है। भारत महत्वपूर्ण खनजियों के लिये आयात पर बहुत अधिक निरिभर है (लथियम एवं निकिल के लिये 100%, जबकि तांबे के लिये 93% आयात निरिभरता)।

Sl. No.	Critical Mineral	Percentage (2020)	Major Import Sources (2020)
1.	Lithium	100%	Chile, Russia, China, Ireland, Belgium
2.	Cobalt	100%	China, Belgium, Netherlands, US, Japan
3.	Nickel	100%	Sweden, China, Indonesia, Japan, Philippines
4.	Vanadium	100%	Kuwait, Germany, South Africa, Brazil, Thailand
5.	Niobium	100%	Brazil, Australia, Canada, South Africa, Indonesia
6.	Germanium	100%	China, South Africa, Australia, France, US
7.	Rhenium	100%	Russia, UK, Netherlands, South Africa, China
8.	Beryllium	100%	Russia, UK, Netherlands, South Africa, China
9.	Tantalum	100%	Australia, Indonesia, South Africa, Malaysia, US
10.	Strontium	100%	China, US, Russia, Estonia, Slovenia
11.	Zirconium(zircon)	80%	Australia, Indonesia, South Africa, Malaysia, US
12.	Graphite(natural)	60%	China, Madagascar, Mozambique, Vietnam, Tanzania
13.	Manganese	50%	South Africa, Gabon, Australia, Brazil, China
14.	Chromium	2.5%	South Africa, Mozambique, Oman, Switzerland, Turkey
15.	Silicon	<1%	China, Malaysia, Norway, Bhutan, Netherlands

■ खनजियों की बढ़ती मांग:

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आगे बढ़ने के लिये बड़ी मात्रा में तांबा, मैग्नीज, जस्ता, लथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे खनजियों की आवश्यकता होती है।
- उल्लेखनीय है कि सौर पीवी संयंत्र या पवन फारम या इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के संबंध में उनके जीवाश्म ईंधन समकक्षों की तुलना में अधिक खनजियों की आवश्यकता होती है।
 - एक पारंपरिक कार की तुलना में एक इलेक्ट्रिक कार को छह गुना अधिक खनजि संसाधनों की ओर ऑन-शोर पवन संयंत्र को गैस से संचालित संयंत्र की तुलना में नौ गुना अधिक खनजि संसाधनों की आवश्यकता होती है।

■ अमेरिका के नेतृत्व वाली MSP की सीमति सदस्यता:

- उल्लेखनीय है कि MSP में चाली, DRC, इंडोनेशिया (जो कुछ महत्वपूर्ण खनजियों से समृद्ध हैं) जैसे देश शामिल नहीं हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिताएँ बढ़ जाती हैं। MSP का मूल आधार 'फ्रेंड शोरिंग' (friend shoring) है, जिसका अर्थ है वनिरिमाण को सत्तावादी एवं अमतिर राज्यों से दूर सहयोगियों की ओर ले जाना।

■ चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ:

- दुर्लभ मृदा तत्व में बड़ी हस्तेदारी: चीन के पास न केवल दुर्लभ मृदा तत्व का एक बड़ा हस्तिसा मौजूद है, बल्कि उसने इन खनजियों की

प्रसंस्करण क्षमता पर भी पूरी तरह से एकाधिकार कर रखा है। चीन वशिव के 35% नकिल, 50-70% लथियम एवं कोबाल्ट और लगभग 90% दुरलभ मृदा तत्व का प्रसंस्करण करता है।

- चीनी कंपनियों ने उन खनियों की प्राप्ति के लिये ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया और DRC में निवास किया है जिनमें स्वयं चीन पर्याप्त रूप से समृद्धि नहीं है।

◦ **तैयार उत्पादों के वनिरिमाण पर एकाधिकार:** चीन ने तैयार उत्पादों के वनिरिमाण पर भी एकाधिकार कायम किया है जहाँ वह दुरलभ मृदा तत्वों से निरस्ति 78% कैथोड, 85% एनोड, 70% बैटरी सेल और 95% स्थायी चुंबक की आपूरत किरता है।

◦ **राजनीतिक प्रतिशोध में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करना:** चीन दुरलभ मृदा तत्वों पर अपने एकाधिकारपूरण स्थिति का उपयोग अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ उनके नियत एवं संबंधित प्रौद्योगिकी को प्रतिबंधित करने के रूप में राजनीतिक प्रतिशोध के लिये कर रहा है।

- महत्वपूर्ण खनियों के कारोबार में चीन की प्रमुख स्थिति और अन्य देशों पर दबाव डालने की उसकी इच्छा ने वशिव समुदाय को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया है।

- **अंतमि उत्पादों के प्रसंस्करण और वनिरिमाण का अभाव:**

- भारत ने ऑस्ट्रेलिया में लथियम और कोबाल्ट संपत्तियों का संयुक्त रूप से पता लगाने के लिये ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समस्या यह है कि खनियों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इसे संसाधन करने और अंतमि उत्पाद का निरिमाण करने की आवश्यकता होती है जिसके लिये प्रौद्योगिकी तक पहुँच आवश्यक है।

- इसकी परयोजना पूरी होने की अवधि (gestation period) लगभग 15 वर्ष या उससे अधिक की मानी जाती है। एक बड़ा भय यह है कि महत्वपूरण खनियों तक पहुँच की कमी भारत के डीकार्बोनाइज़ेशन की दिशा में सबसे बड़ी बाधा सादिध हो सकती है।

महत्वपूरण खनियों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिये कौन-से कदम आवश्यक हैं?

- **संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित करना:**

- संसाधन के पहलू को संबोधित करना महत्वपूरण है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकीयों के लिये आवश्यक महत्वपूरण सामग्रियों की उपलब्धता एवं पहुँच का आकलन करना आवश्यक है। इसमें महत्वपूरण खनियों के घरेलू भंडार का आकलन करना और विधि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से उनके स्थायी निषिकरण या 'सोर्सिं' के अवसर तलाशना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, वैश्वकि आपूर्ति शृंखलाओं में संभावित व्यवधानों से जुड़े जोखियों को कम करते हुए, इन सामग्रियों की नरितर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये रणनीतियाँ विकसित की जानी चाहिये।

- **वित्तीय विचार:**

- **स्वच्छ ऊर्जा की ओर संकरमण के लिये प्रायः बुनियादी ढाँचे के विकास, अनुसंधान एवं विकास और नीति समर्थन में महत्वपूरण निवाश की आवश्यकता होती है।** ऐसे वित्तीयोषण तंत्र, प्रोत्साहन (incentives) और वित्तीयोषण मॉडल की आवश्यकता है **जो सार्वजनिक एवं निजी दोनों निवेशों** को आकर्षित कर सके।
- एक सफल ऊर्जा संकरमण के लिये आवश्यक पूँजी जुटाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों की पहचान करना और नवीन वित्तीयोषण विकल्पों की खोज करना भी महत्वपूरण होगा।

- **प्रमुख चालक के रूप में प्रौद्योगिकी:**

- प्रौद्योगिकी हमारे ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूरण भूमिका नभीती है। वशिव के लिये यह आवश्यक है कि विह घरेलू तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकीयों में नवाचार को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करे।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शक्षिका जगत एवं उदयोग के साथ सहयोग और एक ऐसे पारस्िथितिकी तंत्र के निरिमाण की आवश्यकता है जो नवोन्मेषी स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विकास, अंगीकरण एवं विस्तार का समर्थन करता हो।

- **विशेष निकाय की स्थापना करना:**

- खान मंत्रालय के तहत गठित विशेषज्ञ समिति ने ऑस्ट्रेलिया के CSIRO (जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा खनियों अनुसंधान एवं विकास संगठन है और इस क्षेत्र में वशिव के सबसे बड़े संगठनों में से एक है) की तरज पर देश में महत्वपूरण खनियों पर एक राष्ट्रीय संस्थान या उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता जताई है।
- खान मंत्रालय में एक प्रभाग को महत्वपूरण खनियों के लिये उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यह प्रसंस्करण केंद्र आवधिक रूप से भारत के लिये महत्वपूरण खनियों की सूची को अद्यतन करेगा और समय-समय पर महत्वपूरण खनियों रणनीतिको अधिसूचित करेगा।

उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भारत द्वारा हाल ही में कौन-से कदम उठाये गए हैं?

- **पहचान के लिये एक सुदृढ़ त्रिव्युतीय प्रक्रिया अपनाना:**

- पैनल ने भारत के लिये महत्वपूरण खनियों की पहचान करने के लिये अपने त्रिव्युतीय मूलयांकन के तहत पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विभिन्न देशों की रणनीतियों पर विचार किया।

- दूसरे चरण में विभिन्न मंत्रालयों के साथ उनके क्षेत्रों के लिये महत्वपूरण खनियों की पहचान करने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श का आयोजन किया गया।

- तीसरे चरण में यूरोपीय संघ की कार्यपरणाली का संज्ञान लेते हुए खनियों की गंभीरता का मूलयांकन करने के लिये एक अनुभवजन्य सूत्र प्राप्त करना था, जिसमें दो प्रमुख कारकों- आरथिक महत्वपूरण एवं आपूर्तिजोखियि, पर विचार किया गया।

- **GSI द्वारा किया गया अन्वेषण:**

- खान मंत्रालय से संलग्न एक कार्यालय GSI ने जम्मू-कश्मीर के रयिसी ज़लि के सलाल-हैमना क्षेत्रों में फील्ड सीज़न 2020-21 और 2021-22 के दौरान **G3 स्टेज खनियों अन्वेषण (G3 stage mineral exploration)** किया है और लथियम अयस्क के 5.9

मलियन टन के अनुमानति संसाधन का अनुमान लगाया है।

- मानचित्रण परिणाम के आधार पर भविष्य में जम्मू-कश्मीर सहति देश के वभिन्न हस्तों में लथियम सहति अन्य खनजि संसाधनों पर अन्य कई अन्वेषण कार्यक्रम शुरू कयि जाएँगे।

■ खनजि बदिश इंडिया लमिटेड (KABIL) की स्थापना:

- इसे लथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूरण एवं रणनीतिके प्रकृतिके बदिशी खनजि संपत्तियों की पहचान करने और अधिग्रहति करने का कार्य सौंपा गया है ताकि आपूर्तिपक्ष आश्वस्तसुनिश्चति की जा सके।
- KABIL ने लथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों सहति वभिन्न खनजि संपत्ति हासलि करने के लयि बदिश मंत्रालय और अर्जेंटीना एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में स्थितिभारतीय दूतावासों के माध्यम से शॉर्टलसिट कयि गए स्रोत देशों के वभिन्न राज्य सवामतिव वाले संगठनों के साथ संलग्नता शुरू की है।

नष्टिकरण

महत्वपूरण खनजिओं के संबंध में सरकार की हाल की कार्रवाइयाँ इन आवश्यक संसाधनों की स्थिर आपूर्तसुनिश्चति करने की दशा में एक महत्वपूरण कदम है। नजीि क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लयि खनन कानूनों में संशोधन के साथ-साथ 30 महत्वपूरण खनजिओं की पहचान करना इनकी संभावति कमी को दूर करने की दशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण को परलिकषति करती है। हालाँकि, कुछ देशों में संसाधनों का सकेंद्रण और प्रसंसकरण एवं वनिरिमाण में चीन की प्रमुख स्थितिजैसी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वर्ष 2070 तक डीकारबोनाइजेशन और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग इन चुनौतियों पर काबू पाने और महत्वपूरण खनजिओं की स्थायी आपूर्तसुनिश्चति करने पर निभर करता है।

अभ्यास प्रश्न: सवच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूरण खनजिओं के महत्व और इन संसाधनों की स्थिर आपूर्तसुनिश्चति करने में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. हाल में तत्त्वों के एक वर्ग, जसि 'दुलरभ मृदा धातु' कहते हैं की कम आपूर्तपिर चति जताई गई। क्यों? (2012)

- 1- चीन, जो इन तत्त्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इनके नियात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
- 2- चीन, ऑस्ट्रेलिया कनाडा और चली को छोड़कर अन्य कसी भी देश में ये तत्त्व नहीं पाये जाते हैं।
- 3- दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है इन तत्त्वों की माँग बढ़ती जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

????????:

प्रश्न. "प्रतिकूल प्रयावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन अभी भी विकास के लयि अपरहित है।" विचना कीजिये। (2017)